क्रम संख्या–101 (ग)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 ई0

आश्विन 02, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्याः– 1602/IV(3)/2025–11(03 निर्वा0)/2025

देहरादून, 24 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, स्थानीय निकायों के अतंर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच (Contemporaneous rigorous empirical inquiry) हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 278/2022 (सिविल) सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में निर्वाचन की कार्यवाही के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण कार्य हेतु श्री बी0एस0वर्मा, सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग (Dedicated Commission) गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त मा0 एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल गठन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए होगा।

3– आयोग द्वारा नगर निकायों में निर्वाचन की कार्यवाही के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण करते हुए अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसायें राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– मा0 अध्यक्ष, एकल सदस्यीय आयोग को मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों हेतु अनुमन्य समस्त लाभ/सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

5– शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर उक्तानुसार गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के कार्यालय के लिए कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जायेगा तथा आयोग के सहायतार्थ सचिवालयीय व्यवस्था निदेशालय, शहरी विकास, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कार्मिकों से की जायेगी, जिस हेतु निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के स्तर से कार्यालयीय एवं बजटीय व्यवस्था की जायेगी।

आज्ञा से,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव।

In pursuance of the Clause (3) of article 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the English translation of Notification No. **1602/IV(3)/2025-11(03 EL.)/2025**, dated September 24, 2025 for general information:

No. 1602/IV(3)/2025-11(03 EL.)/2025
Dated Dehradun, September 24, 2025

NOTIFICATION

In compliance with the order dated 10.05.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 278/2022 – Suresh Mahajan vs. State of Madhya Pradesh & Others, regarding a contemporaneous, rigorous empirical inquiry into the nature and implications of backwardness of Other Backward Classes (OBCs) under local bodies and in view of the election proceedings in urban local bodies of the State, the Governor is pleased to allow to constitute the Single-Member Dedicated Commission under the chairmanship of Shri B.S. Verma, retired Hon'ble Judge, Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, for conducting the Other Backward Classes survey as deemed necessary.

2. The tenure of the aforesaid Hon'ble Single-Member Commission shall be for a period of six months from the date of its constitution.

3. The Commission shall conduct a survey of the Other Backward Classes in the context of urban local body elections and shall submit its report and recommendations to the State Government.

4. The Hon'ble Chairperson, Single-Member Commission shall be entitled to all benefits and facilities admissible to retired Judges of the Hon'ble High Court.

5. No additional post shall be created for the office of the above-mentioned Single-Member Dedicated Commission under the Urban Development Department. Secretarial assistance to the Commission shall be provided from the personnel made available by the Directorate of Urban Development, Uttarakhand, based on need. The Director, Directorate of Urban Development shall ensure necessary office and budgetary arrangements.

By Order,

SANTOSH BADONI,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 / आ0श0वि0 / 434–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।